Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

भारतीय परिवारों वैवाहिक और अभिभावक संबंध समकालीन समस्या

Mamta Kumari*

Research Scholar, Venkateshwar University, Gajraula (UP)

सार - *भारत में पारिवारिक अध्ययन पर साहित्य पिछले दो दशकों में काफी हद तक विकसित हुआ है, हालांकि इस तरह के अध्ययन बिखरे हुए हैं। यह लेख भारत में परिवारों पर सामाजिक-जनसांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान के विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करना है, विशेष रूप से परिवार के विकास के क्षेत्र में। भारतीय परिवारों को पिता या माता द्वारा वंश या वंश के अनुसार पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिवार की संरचना को परिवार में भूमिका, शक्ति और स्थिति और संबंधों के विन्यास के रूप में माना जाता है, जो परिवारों के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, परिवार के पैटर्न और शहरीकरण की सीमा पर निर्भर करता है। विवाह पद्धति में विवाह के पैटर्न, शादी के साथी का चयन, शादी में उम्र, शादी के समय शादी की उम्र, शादी की रस्में, वित्तीय आदान-प्रदान और तलाक जैसे विषयों पर जोर दिया जाता है। समकालीन भारतीय समाज में शहरीकरण और औद्योगीकरण के बावजूद, परिवार संस्था लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।*

कुंजीशब्द: *भारतीय परिवार, परिवार का विधान, भारतीय संविधान, पारिवारिक संबंध।*

----------X----------

भारतीय परिवारों का जनसांख्यिकी और संवैधानिक दृष्टिकोण

जनसंख्या और घराने

भारत की जनसंख्या 846 मिलियन (गृह मंत्रालय क्पअपेपवद सामाजिक अध्ययन प्रभाग, 1991) 152 मिलियन घरों में रहती है। इन्हें 112 मिलियन ग्रामीण और 40 मिलियन शहरी परिवारों में बांटा गया है। यद्यपि शहरी आबादी कुल का एक चैथाई है, लेकिन इसकी वृद्धि काफी बड़ी है और परिवार पर इसका बढ़ता प्रभाव अपरिहार्य है। भारत में एक वास्तविक वास्तविकता यह है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुनियादी, नागरिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण जीवन कठोर है। इस तथ्य के बावजूद कि शहरीकरण की गति तेज होने लगी है, भारतीय परिवारों का भारी बहुमत अभी भी ग्रामीण आधारित है और इनमें से 43% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। शहरी गरीब परिवारों में से लगभग आधे लोग झुग्गी (गुलाटी, 1995) में रहते हैं।

गृहस्थों की धार्मिक रचना

भारतीय जनसंख्या को उसकी धार्मिक रचना के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 1981 में, 82.35% के बहुमत वाले हिंदुओं में 11.74% मुस्लिम, 2.44% ईसाई, 1.97% सिख और 1.57% अन्य लोग थे। हिंदुओं को कई जातियों और उप-जातियों में विभाजित किया गया है। यद्यपि धार्मिक रूप से इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जाति विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहार में जाति या जाति जैसे समूह भी उनमें से प्रत्येक में मौजूद हैं।

अधिकांश हिंदू जातियां पितृसत्तात्मक परिवार प्रणाली का अभ्यास करती हैं, हालांकि केरल के दक्षिण-पश्चिमी राज्य में मेले और कुछ अन्य जातियां परंपरा से, मातृसत्तात्मक परिवार प्रणाली द्वारा प्रचलित हैं। इसी प्रकार, उत्तर-पूर्वी भारत में गारो और खासी जनजातियाँ मातृसत्तात्मक हैं, हालाँकि उनकी मातृभाषा, कुछ मायनों में, नायरों से भिन्न है। ष्संयुक्त परिवार से लेकर प्राथमिक किसान तक,ष् यह आधुनिक समय के दौरान भारत में परिवार में परिवर्तनों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का नारा रहा है।

www.ignited.in

भारतीय संविधान के अनुसार परिवार

भारत में विभिन्न धर्मों के परिवारों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं और इसलिए, नागरिक जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में लक्ष्यों पर सहमत नहीं हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी और पारसी, प्रत्येक समुदाय का अपना निजी कानून है जो विवाह और तलाक, गोद लेने, रखरखाव, संरक्षकता और बच्चों की हिरासत, और उत्तराधिकार और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक प्रथाओं के मामलों को कवर करता है। चूंकि ये कानून संबंधित धार्मिक मानदंडों से आकर्षित होते हैं, वे अक्सर पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को बनाए रखते हैं, और सुधारों की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।

यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ष्राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगाष् (पाइल, 1979, पी। 471), धर्मनिरपेक्ष परिवार कानूनों को लागू करने का प्रयास करता है जो पारिवारिक प्रथाओं पर लागू होते हैं। सभी भारतीय हमेशा लंबी और कड़वी बहस से गुजरते हैं। जो कुछ प्रयास सफल रहे हैं, वे धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929य द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1972य विशेष विवाह अधिनियम, 1974य दहेज निषेध अधिनियम, 1961, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में किए गए प्रावधान। हालाँकि, इन कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देते हैं। इस प्रकार, परिवार और उसके सदस्यों के लिए असंख्य नीतियां मौजूद हैं। हालांकि, परिवार के आकार, परिवार के कानूनों, आवास, बच्चों, युवाओं और इसी तरह के लिए अलग-अलग नीतियां, स्वतंत्र उद्देश्य हैं। परिवार के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक समग्र पारिवारिक नीति की अनुपस्थिति में, ये नीतियां कभी-कभी विरोधाभासी और नकारात्मक परिणामों के साथ परिवार को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं।

स्वतंत्रता के बाद के वर्षों के दौरान, आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के परिणामस्वरूप परिवार के आकार, प्रकार और संरचना में परिवर्तन को समझने के लिए भारतीय परिवार पर अध्ययन किया गया। इस अवधि को भारतीय परिवार के विषय में कई कानूनों की विशेषता थी (तालिका 1 देखें)। कानून का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा 1956 में पारित किया गया था, जो उत्तराधिकार से संबंधित था, अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (पाइल, 1979)। इसने एक महिला को विरासत में मिली संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व दिया या उसके द्वारा अधिग्रहण किया। महिलाओं को अब पुरुषों के साथ समान रूप से संपत्ति प्राप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण उपाय थे 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 1969 का तलाक सुधार अधिनियम (पाइल, 1979)।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय परिवारों का जनसांख्यिकी और संवैधानिक दृष्टिकोण पर अध्ययन

2. भारतीय परिवारों में पारस्परिक सम्बन्ध ए वैवाहिक और अभिभावक संबंध एवं विवाह और तलाक

परिवार के लक्षण

अधिकांश जनसांख्यिकीय विशेषताओं, सामाजिक-धार्मिक आस्था और व्यवहार भारतीय परिवार प्रणाली की प्रकृति को प्रभावित करते हैं और इसमें होने वाले परिवर्तनों को भी दर्शाते हैं। भारतीय परिवार संरचना में बड़ा और पितृसत्तात्मक है (कपाड़िया, 1982)। एक पितृसत्तात्मक परिवार में स्थापित, सभी पुरुष सदस्य, अर्थात् पति, बड़े भाई और पिता, परिवार के बाकी लोगों के लिए निर्णय लेने और उनकी शारीरिक और नैतिक सुरक्षा जैसे कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह पितृसत्तात्मक स्थापना, शिक्षित, शहरी मध्यम वर्गों और कुछ ग्रामीण सेट अप (मुलत्ती, 1995) के बीच समानतावादी बातचीत की ओर धीरे-धीरे बदल रही है। यहां तक कि मातृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक संस्कृतियों में भी पितृसत्ता भाई द्वारा धारण की गई शक्ति के रूप में प्रचलित है, न कि स्वयं महिलाओं द्वारा।

पितृसत्तात्मक संरचना, भूमिकाएँ, जिम्मेदारी, नियंत्रण, और परिवार के भीतर संसाधनों का वितरण उम्र, लिंग और पीढ़ी द्वारा सख्ती से निर्धारित किया जाता है। माना जाता है कि परिवार व्यवस्था की स्थापना मुख्य रूप से पूर्वजों की पूजा, एक पुरुष बच्चे को जन्म देने और अगली पीढ़ी को सामाजिक धार्मिक परंपराओं को पारित करने जैसे धार्मिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की जाती है।

पितृसत्तात्मक परिवार पितृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक बने रहते हैंय और वंश पिता के परिवार पर आधारित है। 1954-1956 के हिंदू कोड बिल (जैसा कि पाइले, 1979 में उद्धृत किया गया है) ने बेटी के लिए संपत्ति का कुछ हिस्सा, अंतर-धर्म और जाति विवाह के अधिकार, सम्मान के साथ महिलाओं को समान अधिकार की अनुमति देकर इस प्रणाली

www.ignited.in

में कुछ बदलाव किए हैं। गोद लेने के लिए, तलाक, और पुनर्विवाह।

नारी शक्ति के कुछ बचे हुए गढ़ों में से एक मेघालय की खानियाँ हैं जो परिवार की एक मातृसत्तात्मक प्रणाली के साथ हैं। महिलाओं में विरासत की शक्ति, धन और अधिकार निहित हैं। हालाँकि, बसियावमोहित (1987) ने पाया कि समय बीतने के साथ शिक्षा, तकनीक और राजनीति के कारण मातृ-व्यवस्था में नाटकीय बदलाव आया है। युवा पीढ़ी कुछ प्रकार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है, हालांकि बड़ों को लगता है कि मौजूदा मातृसत्तात्मक रूप जारी रहना चाहिए (साईबोर्न, 1995)।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति में पारंपरिक गौरव के साथ विलय होने वाला नया आर्थिक आदेश है। आज के बड़े कारोबारी घर जैसे टाटा और बिड़ला सभी पारिवारिक उद्यम हैं। इसलिए शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण संयुक्त परिवारों के टूटने के बजाय, शहरी व्यवसाय समुदायों (देसाई, 1980) में अधिक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। विवाहित भाइयों के पास अलग-अलग घर हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यवसाय चलाते हैं और विभिन्न पारिवारिक अनुष्ठानों में नियमित रूप से मिलते हैं। इसलिए, भारत में बड़ी संख्या में परिवारों को अलग-अलग निवास के साथ कार्यात्मक रूप से संयुक्त बताया जाता है।

ग्रामीण भारत में, हालांकि कृषि मुख्य व्यवसाय है, लेकिन बहुत बड़ी भूमि नहीं है। यह, और आधुनिक शिक्षा और अन्य संबंधित कारक, संयुक्त परिवारों को बनाए रखना मुश्किल बनाते हैं (मुलत्ती, 1995)।

वैकल्पिक पारिवारिक पैटर्न

वैकल्पिक परिवार पैटर्न 'शब्द परिवार के पैटर्न का सुझाव देता है, जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण (साथी की मृत्यु, बांझपन) के बाहर व्यक्तिगत परिस्थितियों या पुरुष-प्रवास और महिलाओं की कार्य सहभागिता जैसी कुछ सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों में लोग परिवार के पैटर्न को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं जो उनकी शर्तों के अनुरूप होता है। इसलिए ऐसे परिवार जीवनशैली के प्रयोग मात्र नहीं हैं, बल्कि कुछ परिस्थितियों से बाहर आते हैं (भरत, 1994)। भारतीय संदर्भ में, अधिकांश पारिवारिक विभिन्नताएँ जो आज प्रचलित हैं, ऐसी व्यक्तिगत या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम हैं। प्रायोगिक या चुनी हुई जीवनशैली जैसे बिना शादी के रहना और निःस्वार्थ रूप से संतानहीन लोगों के एक बहुत छोटे समूह तक सीमित है। अलिखित नियम था, और अभी भी है, कि सभी विवाह बच्चों और अधिमानतः पुरुष बच्चों (गुलाटी, 1995) में होने चाहिए। निम्नलिखित को भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली पारिवारिक विविधता माना जा सकता हैरू एकल माता-पिता परिवार, महिला मुखिया परिवार, दोहरे कमाने वाले ध् कैरियर परिवार, निःसंतान परिवार और दत्तक परिवार।

पारिवारिक विविधताओं की सीमा सीमित लगती है। पश्चिम में, परिवार के पैटर्न जीवन शैली के साथ प्रयोग और मौजूदा पैटर्न के लिए विकल्पों की तलाश को दर्शाते हैं। इसके विपरीत, भारतीय पारिवारिक विविधता सामाजिक-आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुकूलन का सुझाव देती है जो अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

विवाह और तलाक

पारंपरिक हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, विवाह एक संस्कार है। औपचारिक शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगीकरण द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आधुनिक रुझानों के प्रभाव की जांच करने के प्रयास में कई अध्ययन किए गए हैं। विवाह, अंतर-जातीय विवाह, अरेंज मैरिज, लव मैच, कुंडली मिलान जैसे क्षेत्रों में बदलते पैटर्न देखे जा रहे हैं। अंतर-धार्मिक विवाह भारत में होते हैं और ऐसे विवाह का समर्थन करने के लिए एक विशेष कानून है। हालांकि, वे संख्या में बहुत कम हैं। अधिकांश लोगों के लिए, विवाह हमेशा एक धार्मिक समूह के भीतर होता है, और परिवार भी, इसलिए इसके भीतर प्रबल होता है। ये धार्मिक समूह इस सदी के कानूनी होने के बाद से विकसित हुए हैं, और कुछ संवैधानिक, संस्थाओं के रूप में भी हैं और इनमें से प्रत्येक में विवाह और परिवार की प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं। हालाँकि संविधान में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशों में से एक यह निर्धारित करता है कि राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, फिर भी सभी धार्मिक समूहों के लिए परिवार और विवाह का एक समान कानून नहीं है। । भारी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए प्रत्येक धार्मिक समूह के भीतर कानून और रिवाज के बीच की खाई। उच्च शिक्षित शहरी समुदायों और जातियों के बीच भी, वृद्धों और अभिभावकों द्वारा प्रमुख मेट चयन पद्धति की व्यवस्था की जाती है, हालांकि धीरे-धीरे यहाँ भी परिवर्तन देखा जाता है।

www.ignited.in

विवाह की ओर युवाओं का मान

समकालीन समाज में विवाह के प्रति लड़के और लड़कियों द्वारा व्यक्त मूल्य बदल गया है। तालिका 4 से पता चलता है कि लड़कियों का ष्बुजुर्गों द्वारा विवाह तय किया जाना चाहिएष् व्यक्त करने में अपने समकक्षों से मतभेद किया। दूसरी ओर, लड़कों ने दृढ़ता से महसूस किया कि विवाह के साथी का चयन उन बयानों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जो समूह उनके मूल्यों में भिन्न नहीं थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सामान्य रूप से विवाह के प्रति मूल्यों में वर्तमान कॉलेज के युवाओं के बीच बहुत बदलाव नहीं हुआ है। वे अभी भी पारंपरिक मूल्यों के साथ समझौते में हैं।

विवाह का आर्थिक मूल्य

विवाह व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालांकि, जरूरतों को पूरा करना आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है जो प्रत्येक साथी शादी में लाता है। लड़कियों में, आर्थिक रूप से अपने पति का समर्थन करने के लिए मजबूत भावनाओं में से एक है।

पारस्परिक सम्बन्ध

वैवाहिक और अभिभावक संबंध

पति-पत्नी का रिश्ता उन रिश्तों के नेटवर्क के बीच बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर एक परिवार घूमता है। स्वस्थ संबंध जीवनसाथी को न केवल अपनी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं बल्कि बच्चों के उचित समाजीकरण में भी मदद करते हैं। दूसरी ओर, वैवाहिक संघर्ष से परिचित अव्यवस्था होती है और बच्चों के पालन-पोषण पर नकारात्मक परिणाम होते हैं। इस प्रकार, एक पति और एक पत्नी के बीच बातचीत की गुणवत्ता पूरे परिवार पर नतीजे है।

माता-पिता-बाल संबंध

अभिभावक-बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक स्वतंत्रता देने वाले दोहरे मानकों के संबंध में संघर्ष करते हैं, एक आवर्ती विशेषता है और कई अध्ययनों में नोट किया गया है (कुरियन, 1986)। एक बालिका को केवल जीवन की छोटी अवधि के लिए एक बच्चा बने रहने की अनुमति है। हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि उसके नटखट घर के साथ उसका रिश्ता अस्थायी है। माता-पिता न केवल भाषण, गतिविधि और खेल को मजबूत करने, बल्कि भारत में भोजन, शिक्षा और अन्य भौतिक संपत्ति के संदर्भ में लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं। सामाजिक रीति-रिवाजों में से कई बाल शोषण का पक्ष लेते हैं या बढ़ावा देते हैं। भारतीय समाज लड़कियों के एक रिश्तेदार को कम आंकता है और उन्हें एक पारिवारिक दायित्व के रूप में देखता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में माता-पिता से कम स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलती है (गदियाली, 1988)।

सहोदर संबंध

करीबी रिश्ते के बीच भाई-बहन के रिश्ते को अनोखा माना जाता है क्योंकि भाई-बहन एक सामान्य आनुवंशिक विरासत और परिवार के भीतर आम शुरुआती अनुभव साझा करते हैं। शुरुआती वर्षों के दौरान भाई-बहनों के बीच भावनात्मक समर्थन के विनिमय पैटर्न की स्थापना की जाती है (एविओली, 1989)। पैतृक अधिकार कमजोर या अनुपस्थित होने पर सहोदर संबंध को भी कलह द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस तरह के संघर्ष भाई-बहन के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हर्जबर्गर और हॉल (1993 ए) ने कहा कि जब भाई-बहन संघर्ष में शामिल होते हैं तो लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग उम्मीदें हो सकती हैं। गंभीर भाई-बहन की हिंसा लड़कों में अधिक प्रचलित पाई गई। इसके अलावा, जब छोटे बच्चे एक बड़े भाई के शिकार होते थे, तो वे माता-पिता से मदद मांगते थे। इस प्रकार, बच्चों ने माना कि छोटे भाई-बहनों के खिलाफ आक्रामकता गलत है (हर्जबर्गर एंड हॉल, 1993 बी)। चूंकि संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की बुनियादी विशेषताओं में से एक है, इसलिए माध्यमिक रिश्तेदारों के बीच सौहार्दपूर्ण और परस्पर विरोधी संबंधों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

सास और बहू के रिश्ते

सास एक प्रमुख स्थान पर रहती है और बहू के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। श्रीवास्तव (1974) ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश (मध्य भारत के राज्यों) की लोक संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में बताया कि दोनों क्षेत्रों में, आमतौर पर सास बहू पर गंभीर नियंत्रण रखती हैं। बड़ी औरत को पता चलता है कि छोटे भाइयों में एकता नहीं थीय युवा पाता है कि बड़े को असहिष्णु रूप से मांग और दबदबा है (मदन, 1965)। बहनों के साथ महिलाओं का रिश्ता एक और क्षेत्र है, जिसमें पढ़ाई की कमी है, हालांकि संयुक्त परिवार में इसका बहुत महत्व है।

समकालीन समस्या

पारिवारिक संबंधों में समस्याएं/वैवाहिक समस्याएँ

वैवाहिक समस्याओं पर अनुसंधान की समीक्षा करने से पहले भारत में वैवाहिक संबंधों, भूमिकाओं और शक्ति के पैटर्न की पृष्ठभूमि आवश्यक है। हालांकि, भारत में परिवार पर अध्ययन आमतौर पर संयुक्त परिवार पर केंद्रित है, पितृसत्तात्मक संरचना के साथ। यह काफी हद तक माना गया है कि संयुक्त परिवार में संयुग्मी संबंधों का बहुत कम महत्व है (रामू, 1988)। नतीजतन, वैवाहिक बातचीत, भूमिका, और शक्ति ने बहुत कम ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में पहचाने जाने वाले कुछ अध्ययनों को समूहीकृत और नीचे वर्णित किया गया है।

वैवाहिक समायोजन बनाम कुप्रथा

वैवाहिक समायोजन आवास की एक स्थिति को संदर्भित करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की जाती है जहां संघर्ष मौजूद हो सकता है। श्रीवास्तव, सिंह और निगम (1988) ने कुछ जनसांख्यिकीय विशेषताओं जैसे कि उम्र के अंतर, विवाह की अवधि, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वैवाहिक समायोजन पर बच्चों की संख्या के प्रभाव का अध्ययन किया। विश्लेषण ने संकेत दिया कि पति और पत्नी के बीच उम्र का अंतर वैवाहिक समायोजन के लिए अत्यधिक योगदान देता है। दूसरे, कुपोषित जोड़ों में जीवनसाथी के शैक्षिक स्तर में अंतर अधिक स्पष्ट था। शुक्ला (1988) ने पाया कि एकल करियर जोड़ों की तुलना में, दोहरे करियर के दंपतियों में से अधिक ने अपेक्षा की कि पति और पत्नी को प्रदाता और हाउसकीपर भूमिकाओं के लिए समान रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, और प्रदाता भूमिका में पत्नियों का अधिक अनुकूल तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। और गृहिणी भूमिकाओं में पति। यह दिलचस्प है, हालांकि, दोनों समूहों में, पत्नियों ने अपने विवाहों में अधिक खुशी प्राप्त की जब वे हाउसकीपर की भूमिका से संतुष्ट थे और प्रदाता भूमिका में अपने पति का अनुकूल मूल्यांकन किया। दूसरी ओर, पति ने संतुष्टि के लिए अधिक महत्व दिया और प्रदाता भूमिका में अपने स्वयं के और उनके जीवनसाथी के अनुकूल मूल्यांकन किया। इस प्रकार, कामकाजी महिला कई भूमिकाओं को निभाती है। इस लेखक के अनुसार, महिला श्रमिकों ने व्यक्त किया कि उनके अपने पति (72%), बच्चों (72%), और ससुराल (22%) के साथ असंतोषजनक संबंध थे। असंतोषजनक रिश्ते के पीछे मुख्य कारणों में पति के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने और अपने बच्चों को पर्याप्त प्यार और देखभाल प्रदान करने के लिए समय की कमी थी। भारी और कभी न खत्म होने वाले काम के कारण शारीरिक और मानसिक थकावट के अन्य कारण थे, अपने पति और ससुराल वालों के प्रति उनके काम के प्रति उदासीन रवैया और महिला श्रमिकों की कमाई पर नियंत्रण पाने में असमर्थता दोनों।

निष्कर्ष

परिवार को समाज की मूल इकाई के रूप में मान्यता दी गई है और यह व्यक्ति और समुदाय के बीच की कड़ी है। परिवार की संरचना पितृसत्तात्मक बनी हुई है। विवाह के पैटर्न में कई बदलाव देखे गए हैं जैसे शादी में उम्र, अंतर-जातीय विवाह, आदि। शहरी क्षेत्रों में तलाक के मामलों में एक सापेक्ष वृद्धि देखी जाती है। यह अतीत में काफी आम था लेकिन उस समय परिवार अधिक स्थिर थे और शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों के लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते थे। वर्तमान रुझानों से संकेत मिलता है कि परिवार की बुनियादी प्रणाली में एक निश्चित बदलाव है, विशेष रूप से पति-पत्नी के रिश्ते में बड़ों की भूमिका और शर्मिंदगी। तलाक की दर पति-पत्नी के रिश्ते की बढ़ती नाजुकता का प्रमाण है। प्रवासन का महिलाओं और बच्चों पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। हालाँकि कई सेट-अप में बच्चे, महिलाएं और बड़ी उम्र के बच्चे विभिन्न अध्ययनों के विषय रहे हैं, फिर भी परिवार की जाँच पूरी तरह स्पष्ट रूप से बहुत सीमित है। ऐसा लगता है कि भारत में लागू परिवार अनुसंधान की एक सामान्य कमी है। इस प्रकार यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या इन अध्ययनों को प्रकृति में लागू माना जा सकता है पे अनुप्रयुक्त अनुसंधान अवधारणाओं के बजाय परिणाम की ओर उन्मुख है, और यह उपयोगिता और अनुप्रयोग के आधार पर शुरू होता है। इसलिए, एक छतरी के नीचे एक साथ लाने की आवश्यकता है, सभी अनुसंधान प्रयास जो परिवार प्रथाओं और परिवार नीति विकास को प्रभावित करने के उद्देश्य से परिवार के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

संदर्भ

1. चेन, एम।, 2000, सदा शोकरू ग्रामीण भारत में विधवा, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

2. चैधरी, जे। एन।, 1988, भारतीय समाज में तलाकरू विवाह विच्छेद और भूमिका समायोजन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, जयपुर: प्रिंटवेल पब्लिशर्स।

www.ignited.in

3. दीवान, पारस, 1983, परिवार कानूनरू भारत में विवाह और तलाक का कानून। नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।

4. ड्रेज, जे।, 1990, विलेज इन रूरल इंडिया श्, डीईपी पेपर नंबर 26। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च प्रोग्राम, एसटीआईसीईआरडी, लंदनरू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।

5. ड्राइवर, ई। डी। और ए। ई। चालक, 1988, व दक्षिण भारत के रूढ़िवादी विवाहों का सामाजिक और जनसांख्यिकीय सहसंबंध ', तुलनात्मक पारिवारिक अध्ययन जर्नल, वॉल्यूम। 19: 229-244।

6. जॉर्ज, पी। ओ।, 2000, श्फोकस के रूप में परिवारश्, द हिंदू संडे मैगजीन, 12 मार्च: 42-43।

7. मान सिंह दास और पैनोस डी। बर्डीस (सं।) में गुप्ता, गिरी राज, 1978, श्संयुक्त परिवारश्। द फैमिली इन एशिया, लंदन: जॉर्ज एलन एंड अनविन, पीपी। 72-87।

8. राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001, नई दिल्ली: योजना आयोग, भारत सरकार।

9. **ILO**, 1996, चाइल्ड लेब: टारगेटिंग द इनटोलरेबल, जेनेवारू इंटरनेशनल लेबर ऑफिस।

10. नायर, पी.टी., 1978, भारत में विवाह और दहेज, कलकत्तारू मिनर्वा एसोसिएट्स।

11. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -1 (1992-93), 1994, भारत: परिचयात्मक रिपोर्ट, मुंबई : **IIPS** और **ORC** मैक्रो।

12. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -2 (1998-99), 2000, भारत: परिचयात्मक रिपोर्ट, मुंबई : **IIPS** और **ORC** मैक्रो।

Corresponding Author

Mamta Kumari*

Research Scholar, Venkateshwar University, Gajraula (UP)